TRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) India-China border trade is presently taking place only from Lipulekh border pass connecting Uttar Pradesh and Tibet. As per information presently available, 251 trade passes have been issued this year as against 21 issued last year during the same period. Report regarding actual trade during this season is not yet available.

(c) Government has already proposed to the Government of People's Republic of China for increasing the number of border trade points.

Impact of Liberalisation of Price Norms on Rice Export

4236. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether new liberalisation of price norms would help to boost rice export;

(b) if so, what are the details of the liberalised price norms issued by Government;

(c) to what extent it has given boost to rice export; and

(d) what are the countries to whom the rice is being exported?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) to (c) The Minimum Export Price of Superfine Non-Basmati rice has been reduced to US $ 225 per Metric Tonne from US $ 250 Metric Tonne with effect from 10-8-1993. It is too early to assess the impact.

(d) Rice is being exported mainly to Saudi Arabia, U. K., U.A.E., Kuwait, Sri Lanka and Malaysia.

Impact of New Commercial Policy on Exporters

4237. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the amount cash compensation due to be paid to exporters and by when payment of the same is likely to be made;

(b) whether it is a fact that exporters have been disappointed from the new commercial policy and that it has had an adverse effect on exports; and

(c) whether Government propose to make any amendment in commercial and export policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The amount of Cash Compensatory Support due to be paid to the exporters is Rs. 200 crores approximately. Against this a sum of Rs. 155 crores has already been released for payment. More funds are likely to be released in September, 1993. All cases of Cash Compensatory Support which are complete in all respects are likely to be cleared by December, 1993.

(b) The scheme of Cash Compensatory Support to Exporters has been suspended subsequent to convertibility of the rupee. No adverse effect of the new commercial policy has been noticed.

(c) Does not arise in view of (b) above.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट

4338. **श्री राम जेठमलानी**: क्या प्रधान मंत्री 5 अगस्त, 1993 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं० 145 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कतिपय कृषि उत्पादों के मूल्यों में निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कृषि उत्पादों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में उत्पादित उत्पादों के निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए कुछ कृषि उत्पादों की निर्यात के लिए पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कृषि उत्पादों के नाम क्या-क्या हैं और उनके निर्यात से प्रति वर्ष कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद): (क) और (ख) निर्यात कीमत वसूली कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे प्राथमिक कीमत, आपूर्ति किए गए सामान की गुणवत्ता, सुपुर्दगी कियान्वयन, मांग तथा पूर्ति की स्थिति और अनेक अन्य घटक इसलिए इसमें

व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकता है । हालांकि सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी वस्तुओं की कीमतों के ब्यौरे नहीं रखती है फिर भी यह विभिन्न मदों की कीमतों पर सामान्य निगरानी रखती है ।

(ग) और (घ) सरकार कृषिजन्य मदों के निर्यात को व्यापक रूप में बढ़ाने को उत्सुक है । इन मदों में उत्तम किस्म के चावल, ताजे फल और सब्जियां, साधित खाद्य पदार्थ, काजू, मसाले, खली, मांस तथा मांस उत्पाद शामिल हैं । सरकार की यह नीति है कि व्यापक उपभोग वाली मदों के निर्यात की अनुमति घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही दी जाए । वर्ष 1993-94 के लिए 2255 मिलियन अमरीकी डालर की कृषि मदों के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है ।

Special Export House Status to State Export Corporation

4239. SHRI KAMAL MORARKA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are considering the grant of Special Export house status to State Export corporations;

(b) if so, whether government have stressed that exports should be taken as a national priority and commitment by States;

(c) to what extent the decision would provide export potential of each State which could be exploited in an effort to improve the country's balance of payment; and

(d) to what extent State Export Corporations would be involved in future ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) and (b) Yes, Sir. Notification in this regard has already issued.

(c) and (d) It would enable the State Export Corporations to enlarge the ambit of their export activity and will encourage the small manufacturers/entrepreneurs to market their goods abroad through them.

मुक्त व्यापार क्षेत्र का योगदान

4240. **श्री अमरनाथ जाजवल्लभ :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1991-92 के वित्तीय वर्ष के दौरान देश के कुल निर्यात में मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों का योगदान बहुत ही कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के योगदान के संबंध में पृथक-पृथक प्रतिबध्दता लक्ष्य क्या-क्या थे और उनके अनुपात में उनका वास्तविक योगदान क्या-क्या था;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान जून, 1993 तक प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित उनके प्रतिबध्दता लक्ष्यों तथा वास्तविक योगदान के संबंध में क्या स्थिति है; और

(घ) उक्त दोनों क्षेत्रों की इकाइयों के ऐसे कितने मामले हैं जिनमें प्रतिबध्दता लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) निर्यातोन्मुख एकक/निर्यात संसाधन जोन के एककों पर उनके आकार, स्थिति, सीमा शुल्क बॉन्डिंग की अपेक्षाओं और उनके अधिकांश उत्पादन के निर्यात-बाध्यित्व की दृष्टि से लगाए गए नियंत्रणों के संदर्भ में देश के कुल निर्यात का 5% (लगभग) योगदान बहुत कम नहीं है । वर्ष 1991-92 के दौरान दोनों योजनाओं के तहत एककों का वास्तविक निर्यात निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)
(अनुमानित)

	लक्ष्य	वास्तविक निर्यात
निर्यात संसाधन जोन	1188	1177
निर्यातोन्मुख एकक	—	1015

(निर्यातोन्मुख एककों के लिए कोई विशिष्ट निर्यात लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है ।)

(ग) और (घ) वर्ष 1993-94 में निर्यात संसाधन जोनों के लिए निर्यात लक्ष्य और अप्रैल-जून, 1993 के दौरान निर्यात नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए)

rhO%h	निर्यात
(1993-94) 2050	(अप्रैल, जून, 1993 के दौरान) 342.66

वर्ष 1991-92 के दौरान निर्यात संसाधन जोनों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में आपूर्ती गिरावट आई थी जोकि मुख्यत : रूपया फुगावान क्षेत्रों को निर्यात के विस्थापन के कारण ।

भारतीय चाय व्यापार निगम के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की बकाया राशियों का भुगतान किया जाना

4241. **श्री चौधरी हरि सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चाय व्यापार निगम के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले चाय बागानों के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि/उपदान की बकाया राशियों का भुगतान करने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चाय कंपनी (तरुण चाय एकक्रें का अधिग्रहण और स्थानान्तरण) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त भुगतान आयुक्त ने विभिन्न श्रेणियों के दावों के निपटान के लिए कार्यभार ग्रहण कर लिया है । इन दावों में टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीयकृत तरुण चाय बागानों के कर्मचारियों को इन बागानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व देय कर्मचारी भविष्य निधि/ग्रैच्यूटी के बकाया के दावे शामिल हैं ।

British Businessmen interest in promoting export of Indian products

4242. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of British businessmen had shown keen interest in joining hands with India for developing marketing, infrastructure and technology for promoting export of Indian products worldwise;

(b) whether they also expressed reservations in regard to implementation of the policy, procedural bottlenecks in relation to the disinvestment of capital since these were repeatedly mentioned by them to the high powered Indian delegation which visited that country recently; and

(c) if so, what is the reaction of Government thereto whether UK firms also express keen interest in investing in India if so, the reaction of Governement thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) Indian and British businessmen have through the recent launch of the Indo-British Partnership Initiative expressed interest in promoting bilateral trade, investment and economic cooperation. Businessmen on both sides highlighted policy and procedural issues having a bearing on such cooperation during the course of a recent visit to Britain of an Indian business delegation.

(c) Such issues are sought to be addressed as a part of the overall liberalisation process. There is a positive trend in British investment in India.

Crop Size fixed by the Tobacco Board

4243. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tobacco Board in the meeting held at Guntur on 24th July, had decided the crop size;

(b) if so, what are the factors that were taken into consideration, while fixing the crop size; and

(c) whether the Tobacco-Board held discussions with traders, exporters and cigarette manufacturers, while fixing the crop size; and if so, what are the details of the discussions held ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) and (b) In its meeting held on 24-7-93 the Tobacco Board fixed a crop size of 52.68 M. Kgs. for Andhra Pradesh and Maharashtra during the crop year 1993-94 taking into account the large carry-over stock, lack of domestic demand and uncertainty in Russian purchases.

(c) The Tobacco Board held discussions with traders, exporters and cigarette manufacturers. These discussions reveled the domestic requirement as 36.80 M. Kgs, carry-over stock from 1992 & 1993 A. P. crop as 28 M. Kgs. and carry over stock from 1992 Karnataka crop as 12 M. Kgs.

Underpricing of Tobacco

4244. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the unit value realisation of